



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

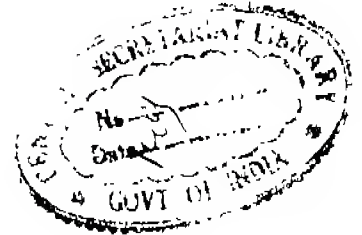
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 547 ]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 1996/आश्विन 8, 1918

No. 547 ]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 1996/ASVINA 8, 1918

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंकिंग प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1996

का.आ. 668 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि. की बाबत 30 सितम्बर, 96 को कारबार की समाप्ति से तारीख 31 दिसम्बर, 1996 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिये अधिस्थगन आदेश करती है और एतद्द्वारा अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, यह भी निदेश देती है कि पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि. को मंजूर की गयी अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना :—

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाय कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :—

- (i) प्रत्येक बचत खाते या चालू खाते या किसी भी नाम से संबोधित किसी अन्य खाते में कुल बकाया के 5000/- रुपये से अनधिक की राशि का भुगतान, बशर्ते कि जमाकर्ता किसी भी प्रकार से बैंक ऋणी न हो, अन्यथा उसे कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा;
- (ii) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्री के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिक्री है तो या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500/- रुपये से अधिक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी;
- (iii) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कम्पनी के प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कंपनी की राय

में आवश्यक है, परन्तु जहाँ किसी कैलेंडर मास में किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छह कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मुद्दे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है और ऐसे में मद पर व्यय 2500 रुपए से अधिक है वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने से पूर्व अभिप्राय की जाएगी;

- (iv) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंदाय रह जाती है; और
- (v) तारीख 30 सितम्बर, 1996 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् वसूल किए गए बिलों की रकम।
- (ख) अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3 केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह भी निदेश देती है कि पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि. उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय, अर्थात् पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि. को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुपंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों या अग्रिमों के प्रसिदाय के लिए मंजूर की गयी राशियों, और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंदाय है, अतिरिक्त संदाय कर सकता है।

4 केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि., पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगा, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि. के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5 केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह और निदेश देती है कि पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि., अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6 केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह भी निदेश देती है कि पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि., ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवरड्राफ्ट के लिए इसके पाम गिरवी रखा गया है, आडमानित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया है :—

- (1) किसी ऐसी दशा में जिसमें, यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मुद्दे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है, और
- (2) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों जो, अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो।

[फा. सं 17/14/96-बी.ओ.ए.]

डी आर. एस चौधरी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**BANKING DIVISION**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 1996

**S.O. 668 (E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section hereby makes an order or moratorium in respect of the Punjab Co-operative Bank Ltd for the period from the close of business on the 30th September, 1996 upto and inclusive of the 31st December, 1996 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act

2 The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it the Punjab Co-operative Bank Ltd shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India —

- (a) grant any loan or advance incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder,
- (i) payment of a sum not exceeding Rs 5,000/- of the total balance in every savings bank or current account or any other deposit by whatever name called, provided that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way,

- (ii) incurring expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2,500/- the permission in writing of the reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred;
- (iii) incurring expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2,500/-, the permission in writing of the reserve bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (iv) payment of the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force, and
- (v) the amounts of the bills received for collection on or before the 30th september, 1996 and realised before, on or after that date.
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties.

3. The central Government hereby also directs that the Punjab co-operative Bank Ltd. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts for repaying loans or advances granted against government securities or other securities, to the Punjab co-operative Bank Ltd. by the reserve Bank of India or the state Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Punjab Co-operative Bank Ltd. shall be permitted to operate its accounts with the Reserve bank of India or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve bank of India or any other bank aforesaid to satisfy that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Punjab Co-operative Bank Ltd.

5. the central Government hereby further directs that the Punjab Co-operative Bank Ltd. may, during the period of moratorium return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The central government hereby also directs that the Punjab Co-operative bank Ltd. may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft :—

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 17/14/96-BOA]  
D.R.S. CHAUDHARY, Jt. Secy.

